प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैः—

(I) इन क्षेत्रों को वित्तपोषित करने के लिए वैकल्पिक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे तंत्र का उद्देश्य वित्त संबंधी आवश्यकता को अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त संरचना एवं इन क्षेत्रों के साथ लेन-देन करने में विशिष्ट कुशलताओं की आवश्यकता के साथ संतुलित करना होगा। जब कभी कुछ क्षेत्रों के लिए रियायती वित्त देने की आवश्यकता हो, तब विशेष रूप से रखी गई आर्थिक सहायता से उसे पूरा किया जा सकता है।

(II) प्राथमिकता क्षेत्र दायित्वों की गणना के लिए आधारिक ऋण को "शुद्ध बैंक ऋण" की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आधारिक वित्त (जब यह एक बार ले लिया जाए) में अन्तर्ग्रस्त बड़ी मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह पूर्णतया अनिवार्य है, क्योंकि इससे वह समग्र ऋण मात्रा बढ़ेगी जिस पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण आधारित है।

(III) मौजूदा शर्त के तहत, प्राथमिकता क्षेत्र दायित्व चालू वित्त वर्ष के 40 प्रतिशत शुद्ध बैंक ऋण से जुड़ा है, जो ऋण योजना की प्रक्रिया में बाधा पहुंचता है। कुशल ऋण संवितरण को सुकर बनाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र दायित्व को पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध बैंक ऋण से जोड़ा जाना चाहिए।

(IV) इस समय प्राथमिकता क्षेत्र के लिए अग्रिम राशियों का वर्गीकरण मुख्यतः आकार के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। इस दल का विचार है कि प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा को विस्तृत बनाया जाना चाहिए ताकि पूर्ण उद्योग/क्रियाकलापों के वर्ग को इसमें शामिल किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अलग-अलग लाभग्राहियों के आकार के कारण अतिरिक्त नियंत्रण लगाए बिना प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किए गए क्षेत्र को समुचित महत्व मिले।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक कार्य दल की सिफारिशों की जांच कर रहा है।

कीमतों में वृद्धि और रुपए का अवमूल्यन

3792. **श्री जनार्दन यादवः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि चालू बजट के बाद आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है;

(ख) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार कौन-कौन से उपाय कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि डालर की कीमत बढ़ रही है जबकि रुपए की कीमत घट रही है; और

(घ) सरकार के पास रुपए की कीमत बढ़ाने के संबंध में क्या योजना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) दैनिक उपभोग की 30 आवश्यक वस्तुओं, जिनकी कीमतें साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से मॉनीटर की जाती है, में से केवल पांच वस्तुओं अर्थात् अरहर, आलू प्याज, रेपसीड/सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, और गुड़ की कीमतों में मार्च, 1998 से तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। शेष आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में केवल मामूली वृद्धि हुई है अथवा उनमें गिरावट ही आई है। दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं, जिनका उत्पादन मौसमी आधार पर होता है, की कीमतें उनके उत्पादन के नतीजों से प्रभावित होती हैं। 1997-98 में रबी की फसल के दौरान बारिश का लम्बे समय तक चला दौर और बाद में अत्यधिक गर्मी का दौर प्याज, आलू तिलहनों, दालों और अनेक अन्य मौसमी फलों और सब्जियों के उत्पादन में तीव्र गिरावट का कारण बना। इस प्रकार उत्पादन में तीव्र गिरावट ही सब्जियों, फलों, खाद्य तेलों और कुछ दालों की कीमत में अधिक मौसमी वृद्धि का मुख्य कारण रही है। बजट का आलू और प्याज तथा अन्य फलों और सब्जियों के भी उत्पादन में गिरावट में प्रभाव नहीं पड़ता है और पड़ सकता था।

(ख) कीमतों में वृद्धि में संतुलन लाने के लिए सरकार द्वारा अनेक नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं। राजकोषीय मितव्ययिता, मुद्रा आपूर्ति वृद्धि में रोक और उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति पक्ष का प्रबन्धन मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अमल में लाए गए मुख्य उपाय हैं। सरकार ने घरेलू उपलब्धता में बढ़ोतरी करने के लिए बड़ी मात्रा में आयात के सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से खाद्य तेल के आयात पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने डी॰एस॰सी॰एस॰सी॰, सुपर बाजार, एन॰सी॰सी॰एफ॰, केन्द्रीय भंडार और मदर डेयरी की खुदरा दुकानों के माध्यम से प्याज और आलुओं की आपूर्ति के लिए एक स्कीम तैयार की है।

(ग) और (घ) जी, हां। जापानी येन, ड्यूश मार्क और फ्रेंच फ्रांक की तुलना में अमरीकी डालर विशेष रूप से जून, 1997 से मजबूत हुआ है जबकि अमरीकी

डालर, यू०के० पौंड, ड्यूश मार्क और फ्रेंच फ्रांक की तुलना में रुपए का अवमूल्यन हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक अल्पावधि में विदेशी मुद्रा बाजार की सुव्यवस्थित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए सट्टेबाजी संबंधी दबाव पर प्रभावशाली नियंत्रण करने हेतु जब कभी भी आवश्यक हो, बाजार में हस्तक्षेप करता है। दीर्घावधिक उपायों में वृहत आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, उत्पादन और उत्पादकता में तीव्र वृद्धि, भुगतान संतुलन की स्थिति संबंधी घटनाक्रम की नियमित मॉनीटरिंग करना तथा चालू खाता घाटे को वहनीय स्तरों पर रखने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपाय करना तथा पूंजी अन्तःप्रवाहों का प्रबन्धन शामिल है।

Takeover of Indian Companies

3793. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) total number of Indian Companies taken over by the Multi-national Companies since 1995 and the amount involved in the takeover;

(b) whether Government have assessed the impact of these takeover; and

(c) if so, the findings thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Financial Support to Prasar Bharati

3794. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government will continue its financial support to the 'Prasar Bharati' without monitoring its performance in the greater national interest;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have set any deadline for framing its own rules, regulations and staff policy by the Prasar Bharati Board; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) and (b) Budgetary support to Prasar Bharati is being provided to meet its expenditure after due scrutiny and examination of its various requirements. The Prasar Bharati Act as it exists does not provide for any day to day monitoring. However, Prasar Bharati are subject to the usual monitoring and review of relevant Parliament Committee and audit.

(c) and (d) Action has been initiated in this regard both by the Government as well as Prasar Bharati.

Proposals for Programmes on Second Channel of Doordarshan

3795. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the details regarding the proposals to use the second channel of Doordarshan exclusively for the telecast of the programmes of the States;

(b) whether Government will consider such a suggestion;

(c) which are the States which gave representations for starting second channel; and

(d) the details of the action taken in this regard?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (d) While there is no proposal to use Second Channel of Doordarshan exclusively for telecast of the programmes of the States, all Doordarshan Kendras originate programmes in their respective Regional Language between 14.30 hrs. to 20.30 hrs. (very recently this has been increased by two hours in each Kendra of Doordarshan). Regional Service gives a complete package of programmes to viewers in each language of the State. Besides this, regional programmes are